पर, यह पता चलता है कि भारत में होटलों के टैरिफ अभी भी यथोचित हैं ।

Economic Crisis in India reduced due to investment by non-resident Indians

1865. SHRI CHITTA MAHATA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that investment made so far by the non-resident Indians in the country has reduced economic crisis in the country ; and

(b) if so, "the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) The main objectives of the scheme offering concessions to non-resident Indians for investment in India are to provide adequate investment facilities for non-resident Indians in India, to attract in that process larger inflow of foreign exchange into India with a view to supporting the country's balance of payments position, and to promote industrialisation. These facilities have resulted in substantial inflows of foreign exchange, particularly in the form of remittances and deposits in non-resident external accounts and foreign currency non-resident accounts. A large number of proposals for investment in industrial units on repatriable and non-repatriable basis have also been approved.

बंद कपड़ा मिलें

1866. **श्री बापू साहिब परूलेकर :**
श्री के० मालन्ना :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंद कपड़ा मिलों की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक दल का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में इस से पहले भी अनेक कदम उठाए थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) देश में बंद वस्त्र की मिलों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों का एक दल बनाया गया है । इस दल में वस्त्र आयुक्त तथा राज्य सरकार, वित्त संस्थान, बैंक, बैंकिंग/एवं क्षेत्रीय वस्त्र अनुसंधान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं । यह दल जांच करेगा कि क्या ये बंद पड़ी मिलें दुबारा चालू करने योग्य हैं, यदि हैं तो इन मिलों को दुबारा चालू करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये ।

(ग) और (घ) गुजरात में बंद/रुग्ण मिलों की समस्याओं की जांच करने के लिये बनाए गए अधिकारियों के दल की सिफारिशों के आधार पर गुजरात में कुछ मिलों के लिए पुदरुद्धार संबंधी अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं । इन व्यवस्थाओं में राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों से मदद और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता का दिया जाना शामिल है ।